जलवायु परविर्तन से नपिटने हेतु सहकारति की आवश्यकता

यह एडटिोरयिल 06/06/2022 को 'द हदिू बज़िनेस लाइन' में प्रकाशति "Greening India Through Cooperatives" लेख पर आधारति है। इसमें जलवायु परविर्तन प्रभावों के शमन में नकिट भवष्यि में वभिन्नि सहकारी समतियिों द्वारा नभिाई जा सकने वाली महत्त्वपूर्ण भूमकिा के संबंध में चर्चा की गई है।

वैश्वकि तापमान में वृद्धि और वशि्व भर में अतरिकि्त जन-वरिोधाभासों के परदृिश्य में जलवायु परविर्तन के प्रमुख प्रभाव के शमन के लयि अभनिव समाधान ढूँढने की आवश्यकता है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अपने अनूठे समाधानों के साथ सहकारी समतियिाँ (Co-operative societies/Co-operatives) जलवायु परविर्तन के जोखमि को कम करने की दशिा में वैकल्पकि समाधान प्रदान कर सकती हैं। पर्याप्त धन और नीतगित समर्थन के साथ सरकार द्वारा उनकी इस भूमकिा में उल्लेखनीय सहयोग दयि जाने की आवश्यकता है।

सहकारी समतियिाँ क्या हैं?

- **सहकारी समतियिाँ या को-ऑपरेटवि (Co-operatives) जन-केंद्रति उद्यम** हैं जनिका स्वामतिव, नयिंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थकि, सामाजकि एवं सांस्कृतकि आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्तकि लयि कयिा जाता है।
- सहकारी समतियिाँ **लोगों को लोकतांत्रकि तरीके से और बराबरी के स्तर पर** एक साथ लाती है। इसके सदस्य चाहे ग्राहक हों, कर्मचारी हों, उपयोगकर्त्ता हों या नविासी हों— सहकारी समतियिों का प्रबंधन लोकतांत्रकि तरीके से '**एक सदस्य, एक वोट**' ('one member, one vote) नयिम के माध्यम से कयिा जाता है।
    - सदस्यों ने उद्यम में कतिनी भी पूंजी लगाई हो, उन्हें एकसमान मतदान अधकिार प्राप्त होता है।

भारत में सहकारी समतियिों का समर्थन करने के लयि सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

- भारतीय संदर्भ में सहकारी समतियिों को **भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 19 के तहत** "**संगम या संघ (या सहकारी सोसाइटी)**" के रूप में शामलि कयिा गया है। आगे फरि भाग **4 में 'राज्य की नीतकि नदिेशक तत्त्व' के अंतर्गत अनुच्छेद 43B को** शामलि कयिा गया जो **सहकारी समतियिों के संवर्द्धन से संबंधति प्रावधान** करता है।
- **संवधिान (97वाँ संशोधन) अधनियिम, 2011** ने भारत में कार्यरत **सहकारी समतियिों के संबंध में भाग IXA (नगरपालकिा) के ठीक बाद एक नया भाग IXB** शामलि कयिा।
- हाल में केंद्र सरकार द्वारा '**सहकार से समृद्धि' (Prosperity through Cooperation) के वज़िन को साकार करने और सहकारति आंदोलन को एक नई प्रेरणा देने के लयि** एक पृथक '**सहकारति मंत्रालय**' का नरि्माण कयिा गया है।

जलवायु परविर्तन शमन में सहकारी समतियिाँ कैसे महत्त्वपूर्ण हैं?

- **सामूहकि और अभनिव समाधान:** सहकारी समतियिाँ सामूहकि रूप से बढ़ते तापमान, नौकरयिों के नुकसान, जल संसाधनों के ह्रास, भूमि एवं वन संसाधनों की गरिावट और अपशष्टिों के संचय के कारण स्वास्थ्य के लयि खतरे जैसे **उभरते प्रभावों के लयि समाधान** प्रदान करती हैं।
- **सर्वसम्मतकि माध्यम से कार्यान्वयन:** सहकारी समतियिों द्वारा पर्यावरणीय-सामाजकि एजेंडे को स्पष्ट रूप से अपनाना **व्यवहार्यता और जीवन शक्तमिें योगदान** करता है; यह समान वचिारधारा के लोगों, हतिधारकों और रणनीतकि सहयोगयिों के लयि सकारात्मक भेदभाव और मज़बूत संबंधों का आधार प्रदान करता है।
- **उत्सर्जन तटस्थ योगदान:** सहकारी समतियिाँ **प्राकृतकि संसाधनों के सतत् प्रबंधन में कई तरह से योगदान** करती हैं।
- **मशिन में नवाचार का योग:** सहकारी समतियिों में अपने **अभनिव कौशल के साथ वास्तवकि दुनयिा की समस्याओं को हल करने** (जैसे समुदायों के लयि स्वच्छ जल का वैकल्पकि स्रोत प्रदान करना) और ऊर्जा पहुँच, ऊर्जा दक्षता एवं नम्नि उत्सर्जन के सतत् लक्ष्यों की पूर्तमिें मदद करने की क्षमता है।

कुछ वास्तवकि उदाहरण

- गुजरात के खेड़ा ज़लि के ढुंडी गाँव ने '**ढुंडी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली' (DSUUSM)** के रूप में **वर्ष 2016 में वशि्व की पहली सौर**

सिंचाई सहकारी समिति की स्थापना की है।
  - इस सहकारी समिति के **सदस्यों को प्रायः 'सौर उद्यमी'** कहा जाता है जो सौर ऊर्जा संचयन (Solar Energy Harvesting) कर रहे हैं।
  - इससे उन्हें बेहतर संचयन में मदद मिली है और वे अतिरिक्त आय के लिये ग्रिड से जुड़े हुए हैं।
- **भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी निगम** (Indian Farm Forestry Development Co-operative- IFFDC), जो **सहकारी समितियों की छत्र संस्था** है, भारत के **तीन उत्तर-मध्य राज्यों- राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में** बंजर भूमि को पुनः वन में रूपांतरित कर रहा है।
- पर्यावरण, जलवायु, जल, स्वच्छ ऊर्जा आदि के संबंध में **स्व-नियोजित महिला संघ (Self Employed Women's Association- SEWA) के** हस्तक्षेप और जागरूकता प्रसार वर्तमान समय के उपयुक्त हैं और वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने वाले हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों (सतत् विकास लक्ष्यों) का समर्थन करते हैं।
- इसके साथ ही **AMUL, IFFCO और NAFED जैसे प्रमुख सहकारी दिग्गजों** के भी उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने **उत्पादन प्रमाणन, खाद्य सुरक्षा के अनुपालन और बाज़ार-संचालित मूल्य शृंखला से संबद्धता के लिये सहकारी समितियों को समर्थन** दे **जैविक खेती में विविधता का प्रवेश** सुनिश्चित किया है।
  - इस तरह की पहल ने सहकारी समितियों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर उन्मुख किया है और वे जैविक उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

सहकारी समितियों के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- **नीति-निर्माताओं द्वारा उपेक्षा:** नीति-निर्माताओं द्वारा **दूरदर्शिता की कमी** के कारण सहकारी समितियों की भूमिका को विभिन्न स्तरों पर अनदेखा किया गया है।
- **जागरूकता की कमी:** व्यावसायिक रणनीतियों और **बाज़ार कार्यकरण के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी** है।
- **वित्तपोषण और क्षमताओं की कमी:** चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हों या निजी क्षेत्र— दोनों ने ही **इस क्षेत्र पर अधिक भरोसा नहीं** दिखाया है, क्योंकि सहकारी समितियों के लिये बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जो उनकी क्षमता को नुकसान पहुँचाता है।
- **खराब प्रबंधन:** बाज़ार के बारे में समझ की कमी और श्रमिकों में कौशल के खराब स्तर के कारण कई सहकारी समितियाँ खराब प्रदर्शन करती रही हैं और **वांछित परिणाम देने में सक्षम नहीं** रही हैं।

आगे की राह

- **सहकारी समितियों की द्वैध भूमिका:** सरकार और कॉर्पोरेट्स सहित विभिन्न हितधारकों को सहकारी समितियों के सबसे उल्लेखनीय **प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ** (यानी एक संगठन और एक उद्यम के रूप में उनकी दोहरी स्थिति) को सामने लाकर उनकी **भूमिका को पूर्णता प्रदान करनी चाहिये और उन्हें आगे और समर्थन देना चाहिये।**
- **आर्थिक, सामाजिक और समाजीय भूमिका:** वे **आर्थिक, सामाजिक और समाजीय भूमिका** (Economic, Social and Societal Role) के रूप में अपनी **तिहरी भूमिका का निर्वहन** करें जहाँ एक ओर लाभ कमाकर और एक व्यवसाय को जीवंत बनाए रखकर **अर्थव्यवस्था का समर्थन** करें, वहीं दूसरी ओर **समृद्धि का सृजन** कर समाज को इसका लाभ देकर अपनी अपनी सामाजिक भूमिका निभाएँ।
- **संवर्द्धित क्षमताओं की आवश्यकता:** सहकारी समिति सदस्यों में संवर्द्धित क्षमताओं की आवश्यकता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के व्यापक प्रभाव को समझ सकें।
- **जागरूकता और कार्रवाई:** पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु सहकारी समितियों की मदद लेने, अनुकूलन एवं शमन पर प्रशिक्षण, मिलकर कार्य करने के लिये गठबंधन का निर्माण और सहकारी उद्यमों एवं नवाचारों में निवेश में **एक हरित एजेंडे का होना आवश्यक** है ताकि संवहनीय भविष्य का निर्माण हो सके।
- **सरकार की भूमिका:** सरकार को उनकी **क्षमताओं के संवर्द्धन हेतु कार्य करना होगा** जहाँ उन्हें **बाज़ार और व्यापारिक समुदायों की ओर से उचित मार्गदर्शन एवं समर्थन** मिल सकना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे एक उद्यम के संचालन हेतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान का वांछित स्तर प्राप्त कर सकें और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में आगे इन क्षमताओं का उपयोग कर सकें।

अभ्यास प्रश्न: "सहकारिता क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं; हालाँकि अब तक इसे इष्टतम रूप से साकार नहीं किया गया है।" इस कथन के आलोक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिये इस क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकने हेतु उपाय सुझाएँ।